साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 01-07 जनवरी 2024 वर्ष-9, अंक-38

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

किसान संघ ने उठाया निलंबित अफसरों की संपत्ति पर सवाल

36 वेयरहाउस ब्लैक लिस्टेट, न तो धान खरीदी जाएगी न ही जमा होगी

भोपाल/जबलपुर। जागत गांव हमार

वेयर हाउस में फर्जी धान उपार्जन मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग ने छह अधिकारियों के निलंबन बाद अब 36 वेयरहाउस को भी ब्लैक लिस्टेट कर दिया है। यह उन 42 वेयरहाउस में शामिल थे, जिनमें उपार्जन केंद्र खोलने की अनुशंसा की गई। इतना ही नहीं जांच दल ने इनके वेयरहाउस में बड़ी मात्रा में फर्जी तरीके से खरीदी गई धान बरामद की गई। हालांकि इस संबंध में जिला प्रशासन को अभी तक आदेश नहीं मिले हैं, लेकिन एमपी वेयरहाउस कार्पोरेशन के पोर्टल में इनके नाम के सामने ब्लैक लिस्ट दर्ज हो गया है। जिसके बाद इनमें न तो अब उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे और न ही धान जमा, पेमेंट भुगतान की जाएगी।

उपार्जन केंद्र बनाने भोपाल भेजे नाम- ब्लैक लिस्ट होते ही कई वेयरहाउस संचालक विधायक से लेकर भोपाल में बैठे अधिकारी और मंत्रियों के पास पहुंच गए। अभी विभाग का मंत्री तय न होने और इस मामले में सीधे सीएम की नजर होने के बाद किसी ने भी मदद करने से इंकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर उपार्जन केंद्र बनाने के लिए भोपाल भेजे गए 42 नामों में से 36 ब्लैक लिस्ट के बाद शेष छह केंद्रों में उपार्जन केंद्र खोलने की स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद अब इन पर भी संदेह खड़ा हो गया है।

ऐसे चला खेल

- हर दिन उपार्जन केंद्र बढ़ते गए, पहले 12 नाम थे, प्रशासनिक अधिकारियों की अनुशंसा पर यह 42 तक जा पहुंचे।
- रात को गोदाम संचालक और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट में बैठकर इन नाम की सूची फाइनल की।
- कई गोदाम संचालक जिम्मेदारी अधिकारियों के बंगले में जाकर अपना नाम जुड़वाने में जुटे रहे।
- गोदाम संचालक की कार से जिम्मेदार अधिकारी भोपाल पहुंचे और लिस्ट फाइनल करने की अनुशंसा तक कर दी।

अब फर्जी पंजीयन की जांच

धान खरीदी में गड़बड़ी सामने आने के बाद अब फर्जी पंजीयन का मामला सामने आ गया है। जिले की 12 सहकारी समितियां में फर्जी पंजीयन हुए। इन्हें गलत तरीके से सिकमीनामे के आधार पर किया गया। इसको लेकर भी अब जांच शुरू हो गई है और कार्रवाई की तैयारी अंतिम चरण में है। वहीं जिले में लगभग 25 फीसदी पंजीयन सिकमीनामे पर किए गए, जिनकी शिकायत भोपाल पहुंच गई है। इनमें प्रमुख तौर पर सेवा सहकारी संस्थान कटंगी से लेकर नुनसर,पनागर, पाटन, बेला, मझौली, तुहारी, सरोद, सहसन, सिहोरा, सिहोरा, लखनपुर सेवा, लमकाना हैं।

उपार्जन में हुई गड़बड़ी के साथ गलत तरीके से सिकमीनामा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 12 में से अभी तक वृताकार सेवा सहकारी समिति मझौली की जांच की जा चुकी है, लेकिन इनमें भी गड़बड़ी सामने आई है।

मीशा सिंह, अपर कलेक्टर, जबलपुर

धान खरीदी की व्यवस्थाएं नहीं सुधारी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बिना पैसे लिए सर्वेयर धान तुलाई के लिए पास ही नहीं कर रहे हैं। निलंबित अधिकारियों की संपत्ति की जांच सीबीआई-ईओडब्ल्यू से कराई जाए।

राघवेंद्र पटेल,प्रांत संगठन मंत्री, किसान संघ के महाकोशल

गोवंश के साथ किसानों की फसलें भी होंगी सुरक्षित

व्हाइट टाइगर सफारी के बाद अब बनेगी 'काऊ' सफारी

भोपाल। जागत गांव हमार

व्हाइट टाइगर सफारी के रूप में सतना जिला पहले ही देश में अपनी पहचान बना चुका है। अब मप्र के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने काऊ सफारी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मझगंवा के जंगल में बगदरा घाटी गोचर के लिए बेहतर जगह है। जहां भारी संख्या में गौ वंश इकट्ठा होता है और 10 हजार गौवंश को संरक्षण मिल सकता है। इससे न सिर्फ गो वंश सुरक्षित होगा बल्कि किसानों की फसल भी सुरक्षित रहेगी। लिहाजा काऊ सफारी के रूप में जल्द गौ-अभयारण्य बनाए जाने की बात कही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि चित्रकूट के बगदरा घाटी में गौवंश संरक्षण के लिए काऊ सफारी के रूप में गौ अभयारण्य विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पुराने समय से गाय के प्राकृतिक रहवास के रूप में जाना जाता रहा है। बगदरा घाटी में सड़क के दोनों ओर 20-20 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल क्षेत्र को फेनसिंग कर वन्य प्राणियों से सुरक्षित किया जाएगा। लगे हुए राजस्व भूमि के 50 एकड़ जमीन पर गौशाला विकसित की जाएंगी। डिप्टी सीएम बगदरा में गौ-अभयारण्य विकसित करने की कार्ययोजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बसामन मामा गौ अभयारण्य की तर्ज पर यहां भी दानदाताओं और जनसहयोग से गौशाला के संचालन में सहयोग लिया जाएगा। गायों के संरक्षण के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 हजार गौमाता के संरक्षण के लिए गौ-अभयारण्य विकसित किए जाने के प्रयास होने चाहिए। प्रभारी कलेक्टर डॉ. परीक्षित झाड़े और जिला वनमंडलाधिकारी विपिन पटेल ने बगदरा घाटी में बनाए जाने वाले गौ अभ्यारण्य की रूपरेखा और कार्य योजना पेश की। गौ-अभयारण्य में बीस हजार गौवंशीय पशुओं को रखने की व्यवस्था की जाएगी। यह भी बताया गया कि बगदरा घाटी के समीप निकटतम ग्राम पिण्डरा और पमनिया जागीर में गौशालाएं संचालित की जा रही हैं। सतना में 90 गौशालाए पूर्ण कर संचालित की जा रही हैं।

उज्जैन जिले के किसान ने किया नवाचार, बाजार में 10 से 12 हजार क्विंटल भाव

मध्य प्रदेश के मालवा में पहली बार होगी राजमा की खेती

उज्जैन। जागत गांव हमार

मालवा के किसान ने नवाचार कर काली मिट्टी में राजमा की खेती करने की शुरुआत कर दी है। जिले में पहली बार राजमा की बोवनी की गई है। इसका उत्पादन 7 से 8 क्विंटल बीघा बताया जा रहा है। बाजार भाव 10 से 12 हजार रुपए क्विंटल हैं। राजमा चीन व ब्राजील की मुख्य फसल मानी जाती है। भारत में भी आपूर्ति इन्हीं देशों से होती है। जिले के किसानों के लिए खेती का एक और रास्ता खुलने जा रहा है। उज्जैन में बाढ़कुमेद के किसान रामेश्वर पाटीदार ने दलहन प्रजाति की फसल राजमा की बोवनी कर नया प्रयोग किया है। जो सफल होता दिखाई दे रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो राजमा का उत्पादन 7 से 8 क्विंटल बीघा का हो सकता है। भाव भी काफी अच्छे 10 से 12 हजार रुपए क्विंटल चल रहे हैं। इसकी खपत दक्षिण भारत, दिल्ली, आंध्रप्रदेश में अधिक बताई जाती है।

भारत में आपूर्ति के मान से राजमा का उत्पादन काफी कम

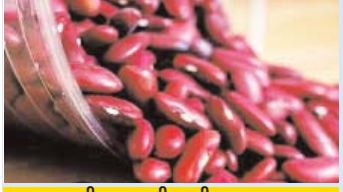

- राजमा चीन व ब्राजील की मुख्य फसल
- भारत में आपूर्ति के मान से राजमा का उत्पादन काफी कम
- राजमा का उत्पादन 7 से 8 क्विंटल बीघा होने की उम्मीद

भारत में आपूर्ति के मान से राजमा का उत्पादन काफी कम होता है। इसकी आपूर्ति चीन, ब्राजील से होती है। किसान रामेश्वर पाटीदार ने बताया कि रबी के सीजन में गेहूं, चना, आलू के अलावा मालवा में कोई अन्य फसल का विकल्प नहीं था। ऐसे में कुछ नया करने के लिए यूट्यूब से राजमा की खेती की जानकारी ली। इसी के सहारे देहरादून से एक व्यापारी से तीन क्विंटल राजमा का बीज लेकर आया। चूंकि राजमा का अभी तक कृषि विभाग के पास कोई प्रमाणित बीज नहीं है। इस बीज को अक्टूबर माह में 20 बीघा खेत में बोया गया। करीब 3 से 4 बार सिंचाई की गई। तीन माह में फसल लहलहाने लगी है। यह तीन माह की फसल होती है। जनवरी के पहले सप्ताह काट कर तैयार हो जाएगी। पाटीदार के अनुसार राजमा की खेती फायदे का सौदा बन सकती है। इसमें लागत खर्च कम है। आलू की खेती का विकल्प भी हो सकती है।

मार्केट की समस्या

वर्तमान में राजमा के लिए कोई थोक बाजार नहीं है। कृषि मंडियों में भी न के बराबर बिक्री के लिए आता है। ऐसे में किसान को खुद बाजार देखना पड़ेगा। हालांकि यह दलहन की प्रजाति है। किराना मार्केट में मांग रहती है। इसका मुख्य उपयोग दाल सब्जी के रूप में होता है। दक्षिण भारत में राजमा को चावल, मछली के साथ खाया जाता है।

खेत से एग्रीकल्चर फीडर की दूरी 200 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए

30 हजार किसानों को मिलेगा कृषक मित्र पंप का कनेक्शन

जबलपुर। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री कृषक मित्र पंप योजना पर प्रदेश में अमल शुरू हो चुका है। किसानों को सिंचाई पंप के लिए कनेक्शन लेने में आने वाले व्यय का आधा हिस्सा ही भुगतान करना होगा। बाकी की रकम प्रदेश सरकार और बिजली कंपनी देगी। इस योजना को लेकर किसानों में इस कदर उत्साह है कि शुरूआत में 20 हजार से ज्यादा आवेदन पहुंच गए है जबकि पहले साल इस योजना में महज 10 हजार किसानों को कनेक्शन दिया जाना है। फिलहाल 3300 आवेदन पर सर्वे हो चुका है। जनवरी अंत या फरवरी तक सर्वे का काम पूरा होने की उम्मीद है। जिसके बाद कृषि पंप के लिए कनेक्शन की प्रक्रिया की जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक मित्र पंप योजना के तहत किसानों को फीडर से खेत तक लाइन बिछाने पर लगने वाले पोल, ट्रांसफार्मर का खर्च उठाना पड़ता है। इसमें लाखों रुपये का व्यय होता है जिस वजह से किसान परेशान होते थे। इसके पूर्व वितरण कंपनी ने मुख्यमंत्री कृषि पंप योजना चालू की थी जिसमें

- दो साल में योजना पर करना होगा काम
- पहले साल दस हजार कनेक्शन होंगे जारी
- 50 प्रतिशत सरकार-कंपनी करेंगे भुगतान

एक मुश्त राशि तय थी इससे ऊपर जो भी व्यय होता था कंपनी और सरकार वहन करती थी। बाद में यह योजना सरकार ने बंद कर दी थी जिसके दोबारा शुरू होने का इंतजार हो रहा था। विधानसभा चुनाव के कुछ माह पूर्व ही मुख्यमंत्री कृषक मित्र पंप योजना को लागू किया गया। इसमें खेत से एग्रीकल्चर फीडर की दूरी 200 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे उपभोक्ताओं को ही इसका लाभ मिलेगा। आवेदन बुलाए गए है जिनका सर्वे किया जा रहा है। यदि नियमों के तहत किसान का कनेक्शन होगा तो उसे सुविधा दी जाएगी।

50 प्रतिशत किसान को व्यय करना होगा

इस संबंध में मुख्य अभियंता परचेस पूर्व क्षेत्र कंपनी संजय भगवतकर ने बताया कि किसानों के कनेक्शन पर आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत किसान को व्यय करना होगा। शेष 40 प्रतिशत राशि सरकार और दस प्रतिशत राशि को वितरण कंपनी देगी। उन्होंने बताया कि अगले साल 20 हजार उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 20 हजार आवेदन पहुंच चुके हैं। संजय भगवतकर ने कहा कि फिलहाल आवेदन पर सर्वे कराया जा रहा है यह काम जनवरी और फरवरी तक पूरा हो जाएगा। इसके पश्चात ही कनेक्शन देने की प्रक्रिया होगी।

यहां इतने आवेदन

जबलपुर संभाग	09 हजार आवेदन
सागर संभाग	9100 आवेदन
रीवा संभाग	1000 आवेदन
शहडोल संभाग	500

-2018 में पड़ाव यूनियन बैंक में कुल 201 केसीसी खाते खोले गए थे

मंडला के किसानों से लोन में फर्जीवाड़ा करने वालों पर अब एफआईआर दर्ज

- तत्कालीन शाखा प्रबंधक और ग्रामीण विस्तार अधिकारी दोषी
- आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर यूनिट ने दर्ज किया केस

मंडला। जागत गांव हमार

किसानों के केसीसी लोन में हेराफेरी करने के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर ने मामला दर्ज किया है। मंडला के पड़ाव स्थित यूनियन बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमित जैन और तत्कालीन ग्रामीण विस्तान अधिकारी अखिलेश मरावी के खिलाफ मामला कायम हुआ है।

वर्ष 2018 और 2019 में किसानों के केसीसी लोन खातों में आने वाली रकम का फर्जीवाड़ा किया गया। मामले की जांच के बाद ईओडब्ल्यू की जबलपुर यूनिट ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक जैन और तत्कालीन ग्रामीण विस्तार अ धिकारी मरावी के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अ धिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

201 केसीसी खाते खोले गए

ईओडब्ल्यू एसपी आरडी भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 2018 में पड़ाव यूनियन बैंक में कुल 201 केसीसी खाते खोले गए, लेकिन इनमें से छह हितग्राहियों की राशि उनके खाने में आने के बाद आं शिक या पूर्ण रूप से ओम रिकवरी एजेंसी के खातों में ट्रांसफर कर दी गई। एसपी भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 2018 में सुबल सिंह के खाते में आई लोन की एक लाख 90 हजार राशि में से 90 हजार रुपये बैसा खिन के खाते में आई तीन लाख 90 हजार रुए की राशि में से तीन लाख 60 हजार रुपये, गोविंद तेकाम के खाते में आए दो लाख में से एक लाख 60 हजार रुपये ओम रिकवरी एजेंसी के खातों में ट्रांसफर की गई।

राशि फिर से उसके खाते में वापस पहुंची

2019 में अनूप सिंह के खाते में आई पांच लाख 50 हजार की राशि में से पांच लाख 34 हजार किसी अन्य खाते में जमा कराए गए। इसके बाद यह राशि फिर से उसके खाते में वापस पहुंची। लेकिन जैसे ही अनूप ने चार लाख आहरित किए गए, तो डेढ़ लाख की राशि उसे नहीं मिल सकी। जांच में सामने आया कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक जैन और तत्कालीन विस्तार अधिकारी मरावी ने खातों में आई रा शि को ट्रांसफर करने के लिए खुद के हस्ताक्षर किए और उक्त राशि का उपयोग भी दोनों ने अपने हित में किया। जिसके बाद दोनों पर प्रकरण दर्ज किया गया।

15 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा प्रोडक्शन

कपास उत्पादन में 8 % की गिरावट का अनुमान

- कपास की खपत 450 लाख गांठ प्रति वर्ष हो जाएगी

भोपाल। जागत गांव हमार

फसल सीजन 2023-24 में कपास का उत्पादन अपने 15 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस सीजन में भारतीय कपास की फसल का आकार 170 किलोग्राम की 294.10 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया गया है। कहा जा रहा है कि कपास उत्पादन में ये गिरावट खराब मौसम और कीट के प्रकोप की वजह से आई है। व्यापार संगठन कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल गनात्रा का कहना है कि कम उत्पादन और अधिक कपास की खपत के कारण हमारी बैलेंस शीट बिगड़ गई है। वहीं, एक्सपर्ट का कहना है कि कपास के उत्पादन में गिरावट आने से महंगाई पर भी असर पड़ सकता है।

उत्पादन बढ़ाना चुनौती

सीएएल फसल समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस सीजन में भारतीय कपास की फसल का आकार 170 किलोग्राम की 294.10 लाख गांठ होने का अनुमान है। हालांकि, यह पिछले साल की तुलना में 8 प्रतिशत कम है और 15 वर्षों में सबसे अधिक कम है। सीएआई द्वारा जारी मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया है कि कपास व्यापार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कपास का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के मालावा में सबसे अधिक कापास उत्पादक किसान हैं। यहां का कपास देश भर में भेजा जाता है। जो अपनी गुणवत्ता के लिए भी जना जाता है।

पैदावार 572 किलो हेक्टेयर

दुनिया में सबसे अधिक कपास की खेती भारत में होती है। दुनिया के कुल कपास रकबे का 33 प्रतिशत भारत के पास है। पूरी दुनिया में कपास का रकबा 329.52 लाख हेक्टेयर है, जबकि यहां पर लगभग 125 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती होती है। खास बात यह है कि भारत में कपास की उपज भी ज्यादा है। 2013-14 में हमारी कपास की पैदावार 572 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई थी।

फसलों की सिंचाई के लिए छोड़ा जा रहा नहरों में पानी

भितरवार। क्षेत्र के किसानों के द्वारा रवि सीजन 2023- 24 के लिए खेतों में बोई गई गेहूं की फसल में सिंचाई के लिए पहले पानी की जरूरत पड़ना किसानों को शुरू हो गई थी, जिसको लेकर क्षेत्र के किसानों के द्वारा निरंतर क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह राठौर से हरसी मुख्य नहर कैनाल और हरसी हाई लेवल नहर परियोजना में गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए पानी छुड़वाए जाने की मांग किसानों के द्वारा की गई थी। जिस पर क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह राठौड़ ने किसानों की मांग को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से दोनों ही नहर परियोजना में हरसी डैम से पानी छोड़ने के निर्देश दिए जिसके आधार पर हरसी डैम से मुख्य नहर कैनाल और हरसी हाई लेवल उच्च स्तरीय नहर में गेहूं की सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। हरसी डैम से निकली मुख्य नहर कैनाल और हरसी हाई लेवल उच्च स्तरीय नहर परियोजना में गेहूं की फसल की पहली सिंचाई के लिए पानी छोड़ने के संबंध में क्षेत्र के भाजपा विधायक ने बताया कि निरंतर क्षेत्र के किसानों के द्वारा बताया जा रहा था कि इस समय पूरे ब्लॉक भर में लगभग 57000 हेक्टेयर में किसानों के द्वारा गेहूं की फसल की गई है। खेतों में गेहूं की फसल है सरसों, चना, मटर, मसूर इत्यादि की फसल को भी सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है। अगर समय से सिंचाई के लिए फसलों को पानी नहीं मिला तो फसल की जो बड़वार है और उसकी उत्पादन क्षमता पर भी विपरीत असर पड़ेगा।

उम्मीदों को पंख

किसान बोले- परंपरागत खेती के मुकाबले चार गुना ज्यादा कमा रहा हूं

स्ट्रॉबेरी से 3 लाख रु. महीने की आमदनी

स्ट्रॉबेरी की खेती ने धार जिले के मनावर के रहने वाले शिवचंद पाटीदार की जिंदगी में खुशहाली भर दी। आज वो सालाना 3.80 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। उनकी आमदनी देख गांव के अन्य किसान भी प्रभावित हुए और वे भी स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करने का मन बना रहे हैं।

धार। जागत गांव हमार

स्ट्रॉबेरी की खेती मध्यप्रदेश में भी बढ़ती जा रही है। इसकी खेती ना केवल ठंडे क्षेत्रों में हो रही है, बल्कि गर्म इलाके निमाड़ के किसान भी इसकी खेती कर रहे हैं। ऐसा ही नवाचार किया है युवा किसान शिवचंद पाटीदार ने। शिवचंद मनावर से 25 किमी दूर जोतपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने यहां पर 4 बीघा खेत में अक्टूबर में स्ट्रॉबेरी की खेती की। पहली बार की खेती में ही परंपरागत खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया।

किसान शिवचंद पाटीदार ने बताया कि मैंने 4 बीघा खेत में 32 हजार पौधे लगाए। मुझे 1 बीघा में लगभग सात हजार 800 पौधों की जरूरत पड़ी। पहली उपज आने तक करीब 90 हजार रुपए प्रति बीघा खर्च आया। इस तरह मुझे करीब 3 लाख 60 हजार रुपए खर्च आया। एक महीने बाद पहली उपज की कमाई 3 लाख 80 हजार रुपए रही। एक फसल से तीन बार उपज निकल सकती है। इस तरह कुल कमाई लगभग 9 से 10 लाख रुपए है। शिवचंद बताते हैं कि मुनाफे की यह रकम दो बीघा के करेला, गराडू और मिर्ची के बराबर है।

हिमाचल में जाकर सीखी खेती

शिवचंद पाटीदार ने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने के पहले दो बार हिमाचल जाकर वहां के किसान, पौधा व्यापारी और वैज्ञानिक से मुलाकात कर थोड़ा कुछ सीखा। अपने क्षेत्र की स्थिति, मौसम, मिट्टी का परीक्षण कर हिमाचल के वैज्ञानिक से जानकारी ली। अभी भी हर दिन वहां के वैज्ञानिक, किसान को स्ट्रॉबेरी के पौधे, फल की इमेज भेजकर स्थिति को बताते हैं। इन्हें देखकर दूसरे किसानों का भी रुझान अब बढ़ना शुरू हो गया है।

पारंपरिक खेती छोड़ स्ट्रॉबेरी को अपनाया

शिवचंद ने कहा कि मैंने पहली बार गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। मैंने पारंपरिक मिर्ची, करेला, सोयाबीन और कपास की खेती करना छोड़ दिया। सिर्फ मुनाफे के लिए मिर्ची, कपास की खेती करता हूं। मैंने जब स्ट्रॉबेरी की फसल लगाने का मन बनाया तो गांव के किसान, रिश्तेदारों का कहना था कि अपनी पुश्तैनी खेती को छोड़कर ये काम क्यों कर रहे हैं? तभी मैंने मन में ठान लिया कि अब स्ट्रॉबेरी की एक नंबर खेती करके बड़ा मुनाफा कामकर दिखाऊंगा। आज गांव वाले और रिश्तेदार मेरी खेती को देखने आ रहे हैं और मीठी स्ट्रॉबेरी खाकर साथ भी ले जा रहे हैं।

हर दो दिन में निकलती है उपज

पाटीदार ने बताया कि स्ट्रॉबेरी एक नकदी फसल है। हर दो दिन के अंतराल में उपज निकलती है, उसे तत्काल मार्केट में बेचना पड़ता है। हमारी उत्पादन क्षमता के हिसाब से हमें दो दिन के अंतराल में 10 हजार रुपए तक आमदनी हो जाती है। इससे खरीफ सीजन की अन्य फसलों में खाद-दवाओं की पूर्ति होकर नकद पैसा जेब में रहता है। स्ट्रॉबेरी की तीन माह की फसल से बड़ा मुनाफा खड़ा कर लूंगा। साहूकारों और बैंक से कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी।

स्ट्रॉबेरी के लिए मल्चिंग पद्धति बेहतर

शिवचंद पाटीदार ने स्ट्रॉबेरी के लिए मल्चिंग पद्धति से खेती को बेहतर बताया है। इसके लिए खेत तैयार होने के बाद पौधे लगाने के लिए बेड बनाते हैं और उस बेड को पॉलीथिन से कवर करते हैं। पॉलीथिन का खर्च प्रति बीघा चार से पांच हजार रुपए तक होता है। हमने अच्छी क्वालिटी की पॉलीथिन ली है, इसलिए रुपए ज्यादा लगे। इसके अलावा फसल में जितना खाद दिया जाए उतना कम है।

आलू की नई किस्म से दोगुना हो जाएगी किसानों की आय

हवा में ही होगी खेती!

भोपाल। जागत गांव हमार

आलू प्रौद्योगिकी संस्थान शामगढ़ में आलू मिट्टी में नहीं बल्कि हवा में उगाए जा रहे हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाई क्वालिटी के बीज किसानों तक पहुंचानें के लिए एयरोपोनिक तकनीक से आलू की नई प्रकार की किस्मों को उगाया है। हाल ही में शामगढ़ करनाल के आलू प्रौद्योगिकी संस्थान ने आलू की एक नई किस्म कुफरी को ईजाद किया है, जो किसानों के लिए वरदान साबित होगी। आलू की ये नई किस्म किसानों की आय को दोगुना कर देगी और लोगों को न्यूट्रिशयन से भरपूर आलू खाने को मिलेगा। जल्द ही किसानों को आलू की ये नई किस्म उपलब्ध करवाई जाएगी।

आलू की खासियत

एयरोपोनिक तकनीक से उगाए जा रहे इस आलू की खास बात ये है कि इसे उगाने के लिए मिट्टी और जमीन की जरूरत नहीं है। किसान इस नई तकनीक से आलू की खेती करने के लिए केंद्र पहुंच रहे हैं। कुफरी नामक आलू की इस नई वैराइटी का बीज किसानों तक नहीं पहुंचा है। अभी इस वैराइटी के आलू एयरोपोनिक तकनीक से सिर्फ शामगढ़ के आलू प्रौद्योगिकी संस्थान में उगाए जा रहें हैं। जब इसके बीज मिनी ट्यूबर्स में बदल जाएंगे, तब इन्हें किसानों को दिया जाएगा।

जरूर बरतें सावधानियां

आलू प्रौद्योगिकी संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि कुफरी किस्म के आलू के करीब 5 से 6 लाख मिनी ट्यूबर्स बनाने का टारगेट है क्योंकि बाजार में इस वैराइटी की काफी डिमांड है। आलू की इस किस्म की खास बात ये है कि ये पिंक कलर के हैं और इसका प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में होता है। आने वाले समय में इस वैराइटी की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगी और किसानों को भी इसका काफी अच्छा रेट मिलेगा।

कम समय में मिलेगी ज्यादा पैदावार

वैज्ञानिकों का कहना है कि आलू की इस किस्म की पैदावार चार से पांच गुना है। इसको उगाने के लिए एयरोपोनिक ग्रोबॉक्स के अंदर माइक्रो प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं और न्यूट्रेंट सॉल्यूशन के माध्यम से दिया जाता है। इसमें मिट्टी और कोकोपिट का उपयोग नहीं होता, हार्डनिंग करने के बाद ट्रांसप्लांट करते हैं। इस वैराइटी की खासियत है कि ये 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। आलू की कुफरी किस्म पुखराज वैराइटी के आलुओं को भी टक्कर दे सकती है। कम समय में ज्यादा पैदावार और अधिक मुनाफा कमाने के लिए आलू की कुफरी उदय वैराइटी किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगी।

मप्र के किसान भी खरीद रहे बीज

आलू प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने बताया कि आलू की इस नई किस्म के बीज लेने के लिए यूपी, मध्यप्रदेश, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों से किसान आ रहे हैं। लेकिन संस्थान की प्राथमिकता हरियाणा के किसान हैं क्योंकि ये खास किस्म उन्हीं के लिए उगाई गई है, ताकि हरियाणा के किसानों को हाई क्वालिटी का बीज मिल सके। एयरोपोनिक तकनीक से नई वैराइटी के आलू का ट्रायल किया जा रहा है, जिनके काफी अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

आलू की नई किस्म

वैज्ञानिकों का कहना है कि संस्थान में कुफरी चिप सोना-1 और कुफरी प्राई सोना जैसी आलू की किस्मों के मिनी ट्यूबर्स भी जनवरी-फरवरी तक उपलब्ध हो जाएंगे। इनका रंग काफी आकर्षक है और कम समय में ज्यादा पैदावार होती है। कुफरी प्राई सोना वैराइटी के आलुओं का उपयोग चिप्स बनाने में होता है।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदियों को जोड़ अटल सपना पूरा करेगी भाजपा

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक और सपना पूरा होने के करीब पहुंच गया है। वर्ष 2004 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में नदियों को जोड़ने की परिकल्पना की थी। उन्होंने 31 रिवर इंटरलिंक्स चिन्हित किए थे, लेकिन अटल सरकार लोकसभा चुनाव हार गई। केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार आने से यह प्रोजेक्ट दस साल तक ठंडे बस्ते में रहा और यह सपना अधूरा रह गया। वर्ष 2014 में दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद एक बार फिर नदी जोड़ो परियोजना की फाइलों को निकाला गया। नदियों को जोड़ने की उम्मीद जागी।

केन और बेतवा नदियों को लेकर जोड़ने को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार में सहमति बन गई है और काम शुरू हो चुका है। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान भी पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) नदियों को जोड़ने के लिए सहमति बनाने के लिए आगे बढ़ गए हैं। इस प्रोजेक्ट से पूर्वी राजस्थान में नई हरित क्रांति की शुरुआत हो सकती है। नए पीकेसी लिंक से पानी के लिए तरस रहे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, करौली, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां में न केवल अगले 30 साल तक पीने का पानी सुचारू रूप से मिलता रहेगा, बल्कि सात लाख हेक्टेयर नई भूमि सिंचित भी होगी। मध्य प्रदेश में मालवा और चंबल क्षेत्र में 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी। इस नए लिंक को राजस्थान में ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) के साथ जोड़ा जाएगा। इसको नया नाम ईआरसीपी-पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट दिया गया है। दरअसल, ईआरसीपी की कवायद वर्ष 2016 में राजस्थान की भाजपा नेतृत्व वाली वसुंधरा राजे सरकार ने शुरू की थी। उन्होंने एक डीपीआर भी तैयार करा ली थी, लेकिन डीपीआर में खामी के चलते प्रोजेक्ट में विलंब हुआ। डीपीआर में सुधार होता, उससे पहले वर्ष 2018 में राजस्थान में सरकार बदल गई। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी तो उसने खामी वाली डीपीआर को ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उस समय मध्यप्रदेश में भी कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन उन्होंने राजस्थान के साथ सहमति नहीं बनाई। फिर यह एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य में अशोक गहलोत सरकार आपस में पानी को लेकर राजनीति में फंसते चले गए। कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में इस मुद्दे को काफी जोर-शोर से उठाया। बजट में कुछ धन भी ईआरसीपी के नाम पर रखा, लेकिन राज्य अपने संसाधनों से इसे पूरा नहीं कर सकता था, यह बात अशोक गहलोत भलीभांति जानते थे। पहले से माना जा रहा था कि यदि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है तो ईआरसीपी-पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट को एक बार फिर गति मिल सकती है। ऐसा हुआ भी। जैसे ही दोनों राज्यों में भाजपा नेतृत्व की सरकार बनी, केंद्र में जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो पहले से इस लिंक प्रोजेक्ट को पूरा करने का वादा करते आ रहे थे, सक्रिय हो गए। अभी राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, लेकिन शेखावत ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करा दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहमति बनाकर बजट स्वीकृत किया जा सकता है। भाजपा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से राजस्थान के 13 जिलों के वोटर्स को साधना चाहती है। यह प्रोजेक्ट नौ लोकसभा सीटों जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, कोटा, दौसा, भरतपुर, धौलपुर-करौली, टोंक-सवाईमाधोपुर, बारां-झालावाड़ पर भाजपा को लाभ पहुंचाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें 90 प्रतिशत राशी यानी 45,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी। शेष 10 प्रतिशत की राशि राजस्थान और मध्य प्रदेश अपने क्षेत्र में होने वाले खर्च में से देंगे। राजस्थान को 3725 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। 5 साल से अटका यह प्रोजेक्ट जब पूरा होगा तो पूर्वी राजस्थान में एक नई हरित क्रांति देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल के बाद देश के शेष 29 रिवर इंटरलिंक्स पर भी सहमति बनाकर काम शुरू जाए।

भारत को उपलब्धियां देकर जा रहा 2023, दुनिया में बजा हमारा डंका

दुनिया के कई हिस्सों में व्याप्त अशांति के बावजूद भारत ने वर्ष 2023 में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। यह न केवल दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया, बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती हुई ब्रिटेन को पछाड़ते हुए दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। अनुमान है कि यदि पहले नहीं, तो 2030 तक यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत ने 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसके तहत 60 विभिन्न जगहों पर 250 से ज्यादा बैठकें हुईं, अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्यता मिली और पहले ही दिन दुनिया भर के नेताओं ने दिल्ली घोषणापत्र पर सहमति व्यक्त की।

जी-20 की अध्यक्षता समाप्त होने से पहले पहली बार भारत ने एक आभासी शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी की। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड, जी-7, आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भागीदारी की और आभासी रूप से शंघाई सहयोग संगठन की एक एवं वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ के दो शिखर सम्मेलनों की मेजबानी की। उन्होंने अमेरिका की सफल राजकीय यात्रा की और अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। भारत संतुष्ट हो सकता है कि उसकी ऊर्जा प्रणाली में नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी 43 फीसदी (172 गीगावॉट) से अधिक हो गई है और वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता 45 फीसदी कम हो जाएगी, जैसा कि ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन में वादा किया गया था। मालदीव में नई सरकार का नेतृत्व मोहम्मद मुइज्जू कर रहे हैं, जो चीन समर्थक हैं। उन्होंने आधिकारिक रूप से भारतीय सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने और अपना हेलीकॉप्टर वापस लेने के लिए कहा है। भारत को इस छोटे, मगर रणनीतिक रूप से अहम पड़ोसी से सावधानीपूर्वक निपटना होगा। चीन के साथ हमारे कामकाजी रिश्ते बने हुए हैं-हम ब्रिक्स, एससीओ एवं जी-20 शिखर सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं। चीन के हांगझोउ में हुए एशियाई खेल में भारत ने 100 से ज्यादा पदक जीते। चीन और भारत के बीच कमांडर स्तर की 20 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर से चीनी सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अपने चीनी समकक्ष के साथ बात करते हुए हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक सीमा विवाद का पूरी तरह से समाधान नहीं होता, तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में चीन की पैठ पर सख्त नजर रखने की जरूरत है। विगत नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी एवं शेख हसीना ने आभासी रूप से सीमा पार अखौरा-अगरतला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, जो पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। इससे अगरतला और कोलकाता के बीच की यात्रा का समय भी कम होगा। जी-20 शिखर सम्मेलन से अलग भारत-बांग्लादेश ने तीन सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के साथ संबंध अभी अनिश्चित बने हुए हैं, लेकिन अफगानिस्तान को भारत की मानवीय सहायता जारी है। एक राष्ट्र के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मणिपुर में जो हुआ, वह फिर कभी न हो। भारत के ओलंपिक विजेताओं को अपनी आवाज सुनाने के लिए हफ्तों तक धरने पर नहीं बैठना पड़ता, उनकी चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, वे सम्मान के पात्र हैं। पन्नून के कारण भारत और अमेरिका के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पटरी से उतरने की संभावना नहीं है। कनाडा खालिस्तानी कट्टरपंथियों का स्वर्ग बन गया है। अमेरिका और कनाडा, दोनों को खालिस्तानी कट्टरपंथियों पर लगाम लगानी चाहिए, जो भारतीय राजनयिकों को धमकी दे रहे हैं। इस साल हुई रिसर्च ने बताया है कि कृत्रिम मेधा यानी एआई अब बीमारियों के निदान और उनके इलाज के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए भी तैयार है।

अयोध्या कृषि विश्वविद्यालय में खुलेगा एग्री टूरिज्म सेंटर

यूपी के अयोध्या स्थित नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर में एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना की कार्यवाही शुरु कर दी गई है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय परिसर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री टूरिज्म मैनेजमेंट पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने के लिए शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। यह कोर्स कृषि के क्षेत्र में बढ़ते भविष्य को देखते हुए शुरू किया जा रहा है। ताकि प्रदेश के हजारों नए स्टूडेंट्स इसका लाभ लेकर स्टार्टअप शुरू कर सकें। दूसरी तरफ राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कृषि क्षेत्र की पूंजीगत योजनाओं के अर्न्तगत विभिन्न मदों में राज्यांश रू 35 करोड़ 94 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या मुख्य परिसर पर एग्री टूरिज्म सेंटर स्थापित किये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री टूरिज्म मैनेजमेंट पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने के लिए शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। वहीं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना परिवर्तित नाम फूड एण्ड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी (कृषि उन्नति योजना) के अर्न्तगत राज्यांश के रूप में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि 8 करोड़ 50 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अर्न्तगत वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि 4200.00 लाख रुपए के सापेक्ष केन्द्रांश की प्रत्याशा में प्रस्तावित राज्यांश धनराशि 8 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनजातीय क्षेत्र उप योजना 2- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश के अर्न्तगत वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि 400.00 लाख रुपए के सापेक्ष भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति की प्रत्याशा में प्रस्तावित राज्यांश धनराशि 8 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सब्जी सहित धान भी जैविक पद्धति से उगाकर खेत से ही होम डिलीवरी कर रहा आधुनिक किसान

60 लाख रुपए का पैकेज भी ठुकराया
जहर मुक्त खेती का जगा रहे अलख

दुबई की चकाचौंध वाली जिंदगी खेती को जैविक बनाने में लगा मठेपुरा का रामदेव

अपनी मातृभूमि की चिंता और राष्ट्र प्रेम क्या होता है यह बात कोई श्योपुर जिले के छोटे से गांव मठेपुरा में रहने वाले इंजीनियर रामदेव माहोर से सीखे जिन्होंने फसलों को रसायन मुक्त बनाने का अभियान छेड़ने के लिए दुबई की चकाचौंध वाली जिंदगी और 60 लाख रुपए के पैकेज को भी छोड़ कर गांव में ही स्थित अपने खेतों में जैविक आधारित खेती शुरू करते हुए अन्य किसानों को भी रसायनिक खेती के नुकसान और जैविक आधारित खेती के लाभ बताना युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है।

श्योपुर। जागत गांव हमार

गरीब किसान परसराम माहौर के घर जन्मे रामदेव ने अपनी पढ़ाई स्कालरशिप और रिश्तेदारों के सहयोग से पूरी की। उनके पिता को रामदेव की पढ़ाई का सपना पूरा करने के लिए अपने खेत भी गिरवी रखने पड़े। परेशानियों को झेलते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी अच्छी रेटिंग को देखते हुए वर्ष 2005 में आदित्य बिरला ग्रुप ने उन्हें 9 लाख के पैकेज पर उड़ीसा में नौकरी करने भेजा, जहां उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें दुबई की कंपनी एमिरेटस्स टैक्स ग्लोबल अल्युमिनियम यूनाइटेड अरब अमीरात ने 60 लख रुपए के पैकेज पर दुबई बुला लिया। वर्ष 2016 से 2020 तक दुबई में नौकरी करने के के बाद राम देव ने अचानक दुबई जैसी विश्व की सबसे चकाचौंध करने वाली सिटी की लग्जरी जिंदगी और 60 लाख के पैकेज को छोड़कर देश और गांव में ही बसने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय से परिजन और रिश्तेदार भौचक थे लेकिन अपनी धुन के पक्के रामदेव ने अपने खेतों में जैविक आधारित फैसले उगाना और इसके लिए अन्य किसानों को भी प्रेरित करने का काम किया जो अनवरत जारी है खेती को रसायन मुक्त बनाने की उनकी इस धुन से जहां कई लोग अचंभित हैं वही कई किसान उनसे प्रेरणा लेकर अपनी जमीनों और जिंदगी को बचाने के लिए जैविक पद्धति अपना रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा के मामले में दुबई की पारदर्शिता ने किया जागरूक

रामदेव को जैविक खेती के लिए दुबई में खाद सुरक्षा के पारदर्शिता वाले कानून ने अधिक जागरूक किया, दरअसल दुबई में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता जिस पर उसको तैयार करने की विधि ना लिखी हो। यानी आपको चावल और गेहूं भी लेना होगा तो उस पैकेट पर उसे तैयार करने की विधि भी लिखी होगी, यानी खेती में कौन सा कौन से रसायन (खाद आदी) का उपयोग किया गया अथवा कीटनाशकों का छिड़काव किया लिखना जरूरी होगा। जबकि हमारे देश में इस तरह के रसायन और कीटनाशकों का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है यही कारण है कि लोगों का शरीर बीमारियों का घर बन गया है। इसी परिपाटी को बदलने की जिद रामदेव को दुबई की चका चौंध वाली लग्जरी जिंदगी से वापस खेतों में ले आई।

ऑनलाइन बेचते हैं जैविक सब्जी

रामदेव अपने खेतों में जैविक आधारित सब्जियां और फसलों का उत्पादन करते हैं इन सब्जियों और फसलों को वह होम डिलीवरी-विक्री करते हैं। इन दिनों खेतों में गाजर मूली पालक मटर मेथी इत्यादि की सब्जियां है जो रामदेव अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों से आर्डर लेकर उनके घरों पर भिजवाते हैं इस तरह जैविक और ताजा सब्जियां सीधे खेत से घरों पर पहुंचने से गृहणियों को भी सब्जी मंडी में आने-जाने की परेशानी से छुटकारा मिल रहा है। रामदेवर ने हाल ही में एक बीघा खेत में जैविक धान का उत्पादन किया था जिसे चावल निकलवा कर उन्होंने 100 रूपए किलो इसी तरह उपभोक्ताओं को होम डिलीवर किया था।

जैविक खेती से होने वाले लाभ

- भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है।
- सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है।
- रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है।
- फसलों की उत्पादकता में वृद्धि।
- बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है।
- जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है।
- भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती हैं।
- भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा।
- भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। भूमि के जल मे स्तर मे वृद्धि क्रिया शील होता हैं।
- मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है।
- कचरे का उपयोग, खाद बनाने में, होने से बीमारियों में कमी आती है।
- फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि
- अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद की जैविक क्रिया बड़ गुणवत्ता का खरा उतरना।

-लैपटाप भी देने की तैयारी में राज्य सरकार
-38 लाख खातेधारक, केंद्र से मांगी अनुमति

अब कोर बैंकिंग से जुड़ेंगी सहकारी समितियां

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश की 4,543 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां जनवरी 2024 तक कोर बैंकिंग से जुड़ जाएंगी। इसके लिए समितियों का कंप्यूटरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 145 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

अब समितियों को लैपटाप देने की भी तैयारी है। सहकारिता विभाग ने तय किया है कि जनवरी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्य का प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि आर्थिक गतिविधियां बढ़ें और इसका लाभ जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के माध्यम से किसानों को ही मिले। प्रदेश में सहकारी समितियों के 38 लाख खातेधारक हैं।

इन्हें ब्याज रहित कृषि ऋण उपलब्ध कराने के साथ खाद-बीज भी दिया जाता है। उचित मूल्य की राशन दुकानों का संचालन भी समितियां करती हैं। कंप्यूटरीकरण न होने के कारण पारदर्शिता नहीं थी। इसके कारण समितियों में कई गड़बड़ियां भी होती थीं।

किसानों के नाम पर गबन

किसानों के नाम पर गबन धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे विश्वास का संकट खड़ा हुआ, जिसके कारण ग्रामीण समितियों से वित्तीय लेन-देन भी नहीं करते थे। जबकि, सावधि जमा पर वरिष्ठ नागरिकों को जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों द्वारा अधिक ब्याज दिया जाता है।

रिकॉर्ड आनलाइन होगा

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कंप्यूटरीकरण होने के बाद हर समिति कोर बैंकिंग से जुड़ जाएगी। सारा रिकॉर्ड आनलाइन होगा और हितग्राही उसे देख सकेगा। इससे विश्वास बनेगा और आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, जिसका लाभ अंतत: समिति के सदस्य किसानों को ही मिलेगा। जनवरी से जागरुकता अभियान भी चलाया जाएगा। केंद्र सरकार से समितियों को लैपटाप देने की अनुमति भी मांगी है। दरअसल, परियोजना को लिए जो राशि स्वीकृत हुई थी, वह बची हुई है। इसका उपयोग राज्य को ही करने देने का प्रस्ताव दिया है।

पीएम जनमन योजना में शामिल किए गए श्योपुर जिले के 249 गांव

स्वास्थ्य, भोजन, रोजगार और मकान, शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाएगी

श्योपुर जिले के 249 सहरिया बाहुल्य गांवों का अब होगा सर्वांगीण विकास

श्योपुर। जागत गांव हमार

जिले के सहरिया आदिवासी बाहुल्य गांवों की आगामी दिनों न केवल सूरत बदल जाएगी, बल्कि यहां के वाशिंदों का भी जीवनस्तर बेहतर होगा। वजह यह है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जनमन योजना में श्योपुर जिले के भी 249 गांवों को शामिल किया गया है। सहरिया आदिवासी बाहुल्य इन 249 गांवों में 42 बिंदुओं के आधार पर सर्वे चल रहा है और 215 में सर्वे पूरा हो चुका है। इस योजना के तहत आदिवासियों के बेहतर स्वास्थ्य, भोजन, रोजगार और मकान, शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाएगी।

आदिवासी समुदायों की तस्वीर बदलेगी सरकार- बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मकान आदि जैसे लाभ दिया जाएगा, जिसके लिए भारी भरकम बजट भी निर्धारित किया गया है। पीएम जनमन के तहत सरकार ने देश के 22 हजार से अधिक गांवों में रहने वाले लाखों की आबादी वाले 75 आदिवासी समुदायों और आदिम जनजातियों को लाभ पहुंचाने के लिए पहचान की है। योजना से सरकार आदिवासी जीवन स्तर की तस्वीर बदलने की कोशिश में है। योजना के तहत आदिवासी समुदायों की जीवन स्तर को बेहतर किया जाएगा। इसके लिए मासिक राशन सुविधा, चिकित्सा बीमा, गारंटी रोजगार, नल जल, उज्ज्वला योजना, मकान और जमीन समेत कई तरह के लाभ दिए जाएंगे।

सर्वे में शेष रहे 34 गांव

योजना के नोडल अधिकारी और सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण एमपी पिपरैया ने बताया कि योजना के तहत जिले में 249 सहरिया बाहुल्य गांव चिन्हित किये गये है, जिनमें 215 ग्रामों में सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है, शेष 34 गांव सर्वे कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि 42 बिन्दुओं पर सर्वे की कार्यवाही की गई है तथा शिक्षा, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, पीएचई, विद्युत, ग्रामीण विकास विभाग आदि से बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के प्रस्ताव लिए जा रहे हैं।

गांवों में बनेंगे मल्टीपरपज सेंटर

जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए बीती शाम कलेक्टर ने भी बैठक ली। जिसमें चिन्हित सभी सहरिया बाहुल्य ग्रामों में सर्वे का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत बनाए जाने वाले मल्टीपरपज सेंटर जिनमें स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र आदि एक ही परिसर में होंगे। यह कार्य बड़े-बड़े ग्रामों में लिए जा सकते हैं।

-धड़ल्ले से इंदौर-दिल्ली में बिक रही हल्की क्वालिटी की गजक

मुरैना के गजक कारोबारियों को जीआइ टैग का फायदा नहीं मिल रहा

मुरैना।

मुरैना की गजक को जीआई टैग मिलने के बाद यह गजक का पहला सीजन है, जो लगभग आधा बीत चुका है। लेकिन जीआई टैग से होने वाले फायदों का अंश मात्र भी लाभ अब तक मुरैना के गजक व्यापारी, कारीगर और इसके उद्योग को नहीं मिल सका है। पहले की तरह आज भी दूसरे शहरों में मुरैना के नाम से धड़ल्ले से गजक बिक रही है, जो अब गैर कानूनी है। गौरतलब है, कि 27 मार्च 2023 को मुरैना की गजक को जीआई टैग मिला था। इसी दिन मुरैना की गजक के साथ ही मप्र के रीवा के सुंदरजा आम, छत्तीसगढ़ के धमतरी के नागरी दुबराज चावल को भी केंद्र सरकार ने जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग मिलने के बाद गजक को मुरैना विशेष उत्पाद माना गया है, यानी अब देश-विदेश में कोई अन्य शहर में गजक को मुरैना की गजक या फिर मुरैना के प्रसिद्ध व्यापारियों के नाम से नहीं बेच सकता।

कारोबारियों को नहीं मिल रहा फायदा- सर्दी के दिनों में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल से लेकर दिल्ली, जयपुर, गुजरात, मुंबई, कोलकाता तक में गजक की दुकानों पर मुरैना गजक लिखकर उसे ग्राहकों को दिया जा रहा है, जो गलत है। जीआई टैग मिलने के बाद इस पर अंकुश लगना था। इसका सीधा फायदा मुरैना के गजक कारोबार को होता और फिर अन्य शहरों में मुरैना की गजक को ही मुरैना के नाम से बेच सकते थे, इससे जिले में गजक कारोबार में कई गुना बढ़ोतरी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जीआई टैग के बाद शासन-प्रशासन ने मुरैना के गजक की वैरायटियां, गजक कारोबारी व इसे बनाने वाले कारीगरों तक का दस्तावेज बना है, नहीं कोई आधिकारिक संगठन। कमाल की बात यह है, कि कईयों पुराने दुकानदारों को यह नहीं पता कि जीआई टैग क्या होता है और यह हमारी गजक को मिल चुका है।

100 साल का रिकॉर्ड बनाया- मुरैना की गजक को जीआई टैग दिलाने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांच साल पहले की थी, इसके बाद साल 2019 में तत्कालीन कलेक्टर प्रियंका दास ने मुरैना में गजक महोत्सव मनाया, जिसमें जिलेभर के गजक कारोबारियों की दुकानों का मेला लगा। इस महोत्सव में देश के कई हिस्सो से लोग आए। इसके बाद कलेक्टर प्रियंका दास ने ही जीआई टैग के लिए मुरैना की गजक का दावा ठोका। करीब पांच साल तक इसके लिए जिला प्रशासन के साथ उद्योग एवं व्यापार केंद्र ने मशक्कत की। मुरैना के पानी से लेकर गजक बनाने में उपयोग होने वाली तिली व गुड़ की लैबों में जांच करवाई गई। मुरैना के गजक कारोबारियों ने गजक एसोसिएशन नाम से संगठन बना, जिसने मुरैना की गजक से जुड़े 100 साल से ज्यादा पुराने रिकार्ड की 160 पेज से ज्यादा की फाइल तैयार की थी। इसमें 90 से 100 साल तक के पूर्व गजक कारोबारी व कारीगरों के अनुभव आदि थे। जीआई टैग के लिए पांच साल में मुरैना, ग्वालियर, भोपाल और दिल्ली तक कईयों बैठकें चलीं, तब यह तमगा मुरैना की गजक को मिल सका।

- जीआई टैग मिल तो गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। अधिकांश व्यापारियों को इसकी सही जानकारी नहीं। ग्वालियर, आगरा से लेकर दिल्ली, मुंबई आदि शहरों में मुरैना के नाम से अब भी गजब बिक रही है, जो बेहद हल्की गुणवत्ता की होती है। यह नकली दुकानदार मुरैना के गजक कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जीआई टैग मिलने के बाद सबसे पहले इसी पर अंकुश लगना था, पर अब तक कुछ हुआ नहीं।

-आकाश शिवहरे, सचिव, गजक एसोसिएशन मुरैना

- जीआई टैग की बातें तो चल रहीं थीं, लेकिन अब तक यह मिला नहीं है।अगर जीआई टैग मिल जाता तो हमारे व्यापार को कुछ तो सरकारी सहूलियत मिलती, सब कुछ पहले जैसा है। मेरे बाबा सीताराम शिवहरे ने मुरैना में गजक का आविष्कार किया, 2019 में हुए गजक महोत्सव में हमारी गजक को प्रथम पुरस्कार मिला था।

-सूरज शिवहरे, गजक कारोबारी

-सरकार नहीं दे रही ध्यान, 25 से 30 किसान की कर रहे खेती

चंदेरा का पान खो रहा पहचान! बर्बादी की कगार पर पहुंची खेती

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

मौसम के लगातार खराब रहने शीतलहर, कोहरा होने से पान की खेती करने वाले कृषक की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। जिले के चंदेरा का देशी पान पाकिस्तान, नेपाल, अरबी देशों में जाने के लिए मशहूर था। जो पिछले पांच सालों में घट कर मात्र 25 प्रतिशत ही रह गया है। वहीं रही सही कसर पिछले कई दिनों से चल रही शीतलहर ने पूरी कर रही है। पान की यह लालिमा मौसम की भेंट चढ़ रही है। मौसम की बेरुखी के चलते पान की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। जिससे किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। किसान बेरोजगार होकर महानगरों की ओर रुख करने को विवश है। गौरतलब है पान की खेती को करने वाले किसान बड़ी मेहनत से इसे पैदा करता है। खेतों के चारों ओर नेट या सनौगा की छह फुट ऊंची दीवार के साथ ऊपर के हिस्से में बांस व घास-फूस मंडपाकार बनाया जाता है। ताकि पान को गर्म व सर्द हवाओं से बचाया जा सके। खेत के नजदीक ही 10 से 15 फिट लंबा चौड़ा गड्ढा कर पानी संरक्षित किया जाता है। इतना ही नहीं पान के आसपास जहरीले सांपों का डेरा भी रहता है। इनसे बचना मुश्किल होता है लेकिन रोजी रोटी की खातिर किसान को यह खतरा भी मोल लेना पड़ता है।

किसानों को हो रहा भारी नुकसान

पान खेती से किसानों का लगातार मोह भंग होता जा रहा है। जहां ग्राम के लगभग तीन सौ किसान इस धंधे से जुड़े थे, वहीं वर्तमान में इनकी संख्या महज 30 रह गई है। जिसका एक प्रमुख कारण पान की खेती को कृषि का दर्जा न होना है। जिससे इसकी खेती करने वाले कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग की नजरो मे कृषक ही नहीं माने जाते। प्राकृतिक आपदा की मार और विभाग द्वारा जानकारी न देने के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

खेती चौपट होने के कगार पर

किसानों ने बताया कि गांव में सभी पान की खेती करते है। यह हमारे पूर्वजों के द्वारा विरासत के रूप में दिया गया व्यवसाय है। पान की खेती में लाखों की लगाई है पर मुनाफे का समय आया तो प्राकृतिक आपदा के चलते यह पान की खेती चौपट होने के कगार पर है। बनारसी पान, मद्रासी, कपूरी, सुहागपुरी, रामटेकी और महोबिया के साथ चंदेरा का देशी पान अपने आप में बहुत खास है जो औषधीय गुणों से युक्त है। लेकिन शासन प्रशासन की बेरुखी के कारण मात्र 20 से 25 किसान ही अब इसकी खेती कर रहे है।

पड़ोसी देशों में मांग

संदीप बालाराम चौरसिया ने बताया कि गांव के देशी पान की पड़ोसी देशों में भी बड़ी मांग रही। बुंदेलखंड में जिस देशी पान की मिठास के कायल मुम्बई, लखनऊ, दिल्ली, नेपाल, पाकिस्तान और कई महानगर हुआ करते थे।वही उसकी खेती अब शासन प्रशासन की अनदेखी से विलुप्ति की कगार पर है।

किसानों को नहीं दी जा रही सहायता

चौरसिया समाज के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष एनडी चौरसिया ने बताया कि शासन स्तर पर अभी तक पान किसानों को किसी प्रकार से सहायता नहीं दी जा रही है। जिससे इसकी खेती करने वाले किसानों में निराशा छाई हुई है। हाल ही में शीतलहर और कोहरे के कारण पान डंठल से गिरने लगा है, जिससे यह खेती बर्बाद हो गई है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किसी योजना का लाभ नहीं दिया जाता है, जिससे पान कृषक भारी नुकसान उठा रहे हैं।

पान किसानों को समय समय पर जानकारी दी जाती है। यह सही है कि उन्हें तीन साल से पान की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी नहीं मिली है। जिसका कारण यह है कि किसानों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन कराने के बाद जीएसटी के बिल विभाग को प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। जिससे उन्हें अनुदान नहीं मिल पाया है।

-धर्मेंद्र मोर्या, उद्यानिकी अधिकारी, जतारा

-पाले में मटर को लग सकता ये रोग

गिरते तापमान के कारण मटर में इन रोगों का हो सकता है अटैक

भोपाल।

कोहरे और ठंड से पिछले सप्ताह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे के कारण दलहनी फसल जैसे कि मटर पर पाले का असर पड़ सकता है। घने कोहरे के ठंड के कारण दलहनी फसलों में कई रोग का अटैक होता है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। इन रोगों के कारण फसलों के फूल और फलियां सूख सकती हैं, जिससे पैदावार कम होने की आशंका होती है। इसलिए किसानों को सुझाव दिया जा रहा है कि इस समय वे रोगों की रोकथाम के उपायों पर ध्यान दें। डॉ एसके सिंह, पौध सुरक्षा विशेषज्ञ, आरए यू पूसा, समस्तीपुर के पादप रोग विभाग के हेड ने बताया कि लगातार कोहरा और गलन मटर की फसल के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। कोहरे और गिरते तापमान के कारण फसल की बढ़वार कम हो जाती है। इस समय किसानों को फसल के रख-रखाव में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कोहरे और गलन के कारण तापमान कम होने पर फसल में मृदुरोमिल आसिता रोग रोग (पाला) लगने का खतरा बढ़ जाता है। मृदुरोमिल आसिता रोग के लक्षणों के बारे में बताया जाता है कि इस रोग के लगते ही फसल की पत्तियां किनारों से भूरी हो जाती हैं और सूखने लगती हैं। मृदुरोमिल आसिता रोग से बचाव के लिए मैंकोजेब दवा का ढाई ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर किसान सुरक्षात्मक छिड़काव कर सकते हैं। दोनों दवाओं का बारी-बारी से हर 10 से 15 दिन में छिड़काव करना फायदेमंद रहता है। इसके साथ ही खेत में बराबर नमी बनाए रखने का प्रयास करें। इससे फसल में सुधार और फायदा होगा।

गलन रोग के लिए मौसम अनुकूल

इस समय मटर में रूट रॉट रोग यानी कि आर्द्र गलन रोग भी फैलता है। वातावरण में अधिक आर्द्रता होने पर यह रोग ज्यादा तेजी से फैलता है। मटर की फसल को इस रोग से काफी नुकसान होता है, लेकिन अगर इस रोग का सही तरह से प्रबंधन किया जाए तो बेहतर उपज मिलती है। आमतौर पर इस रोग का प्रकोप छोटे पौधों में अधिक देखने को मिलता है। ये रोग के लिए सबसे अनुकूल मौसम होता है। दरअसल इसके लक्षण प्राय: बाढ़ वाले या जलजमाव के इलाकों में ज्यादा देखे जाते हैं। इस रोग से प्रभावित पौधों की निचली पत्तियां हल्के पीले रंग की होने लगती हैं। कुछ समय बाद पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। पौधों को उखाड़ कर देखा जाए तो उसके जड़ सड़े हुए दिखते हैं। रोग से प्रभावित पौधे सूखने लगते हैं। इससे उत्पादन में भारी कमी आती है।

इन दवाओं का करें इस्तेमाल

अगर इस समय रोग दिखाई दे रहा है और आपको जैविक नियंत्रण करना है तो ट्राइकोडर्मा की 10 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल कर प्रयोग करें। मटर की जड़ों की सड़न पर नियंत्रण पाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर रोग तेजी से फैल रहा है तो रोको एम या कार्बेंडाजिम नामक कवकनाशक की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर मिट्टी का उपचार करने से रोग की उग्रता में भारी कमी आती है।

पहले से ही रहें सावधान

इन रोगों से बचाव के लिए हमेशा प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त बीजों का ही प्रयोग करें। बुवाई के लिए प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। उचित जलनिकासी वाले खेत का चयन करना सुनिश्चित करें। पौधे विकास की शुरुआती अवस्था में, विशेषत: ठंडी में फॉस्फोरस की संतुलित मात्रा में प्रयोग करें और खेत में जलजमाव की स्थिति न होने दें।

किसानों और ग्राहकों को कीमतों में राहत मिलने का अनुमान

देश के चीनी उत्पादन में सुधार की उम्मीद

भोपाल। अक्टूबर-दिसंबर सीजन के दौरान चीनी उत्पादन में 9 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन सहकारी चीनी इंडस्ट्री बॉडी नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री ने वर्तमान सीजन में चीनी उत्पादन में सुधार की उम्मीद जताई है। सहकारी निकाय ने चालू सीजन में 30.5 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान जताया है। इससे किसानों को बेहतर कीमत हासिल हो सकेगी और चीनी की खुदरा कीमतों में नरमी रहेगी। सहकारी चीनी उद्योग निकाय ने चालू सीजन में चीनी उत्पादन का अनुमान 29.15 मिलियन टन से बढ़ाकर 30.5 मिलियन टन कर दिया है। क्योंकि चालू सीजन का उत्पादन घाटा 31 दिसंबर तक 8 प्रतिशत से कम हो गया था, जबकि 15 दिसंबर तक यह घाटा 9 फीसदी से ज्यादा था। सहकारी निकाय ने इस रिकवरी में और बढ़ोत्तरी की उम्मीद जताई है। कहा है कि दिसंबर के आंकड़े सुधार के संकेत दिखा रहे हैं। सहकारी निकाय के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवरे ने कहा कि सीजन की शुरुआत में अनुमानित 29 मिलियन टन चीनी उत्पादन में लगभग 1.5 मिलियन टन की बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल उत्पादन पर मौजूदा प्रतिबंधों में कुछ हद तक ढील दी जा सकती है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा विनिर्माता संघ के साथ मिलकर इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाएगा।

511 कारखानों में पेराई हुई

सहकारी चीनी निकाय के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 सीजन में अक्टूबर और दिसंबर के बीच 511 कारखानों ने 122.26 मिलियन टन गन्ने की पेराई की है और 9.17 प्रतिशत की औसत चीनी रिकवरी के साथ 11.21 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया है। एक साल पहले इसी अवधि में 514 मिलों ने 132.06 मिलियन टन गन्ने की पेराई की थी और 9.19 प्रतिशत की औसत चीनी रिकवरी के साथ 12.14 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया था।

इस्तेमाल सीमित करने का असर

सहकारी निकाय के प्रबंध निदेशन ने कहा कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी चीनी की पैदावार और बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गन्ने के रस से इथेनॉल का उत्पादन सीमित कर दिया है। ऐसे में स्थानीय खपत के लिए देश में चीनी की कुल उपलब्धता शुरुआती अनुमानों से अधिक होने की उम्मीद है। निकाय ने पूर्ववर्ती अनुमानों में संशोधन किया है।

राज्यवार चीनी उत्पादन अनुमान बढ़ाया

सहकारी चीनी उद्योग निकाय के अनुसार उत्तर प्रदेश में 11.5 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है। पहले राज्य में 11 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। वहीं, महाराष्ट्र में 8.5 मिलियन टन के पूर्व अनुमान को बढ़ाकर 9 मिलियन टन किया गया है। कर्नाटक में 3.8 मिलियन टन पूर्व अनुमान को बढ़ाकर 4.2 मिलियन टन कर दिया गया है। इसी तरह तमिलनाडु में 1.2 मिलियन टन और गुजरात में 1 मिलियन टन चीनी उत्पादन की उम्मीद है जताई गई है।

नौकरी नहीं मिली तो नहीं चलने देंगे ट्रेन

मुंबई के रेल सुरक्षा आयुक्त को रीवा के किसानों ने दी चेतावनी

रीवा। जागत गांव हमार

ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत नव निर्मित गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन गत दिवस पुलिस छावनी में तब्दील रहा। ललितपुर सिंगरूली रेल मार्ग के अंतर्गत रीवा से गोविंदगढ़ रेल मार्ग का निरीक्षण करने मुंबई रेलवे सर्किल के सीआरएस रेलवे सुरक्षा आयुक्त मनोज अरोरा कड़ी सुरक्षा के बीच रीवा के गोविन्दगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे। आरपीएफ सहित जिले के तमाम थानों का पुलिस बल साथ ही दो एडिशन एसपी और अपर कलेक्टर भी तैनात रहे। दरअसल, यहां पर पिछले एक वर्ष से किसान आंदोलनरत हैं। उनकी मांगें हैं कि रेलवे ने किसानों की जमीनें अधिग्रहण के बदले परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन रेलवे ने वर्ष 2019 में नियमों पर बदलाव किया और किसानों के साथ वादा खिलाफी की। दरअसल ललितपुर सिंगरोली रेल परियोजना के अंतर्गत किसानों की जमीनें अधिग्रहण की गई थीं, ताकि रेलवे लाइन का विस्तार किया जा सके। जमीन अधिग्रहण के दौरान रेलवे के अधिकारियों ने किसानों से वादा किया था कि उन्हें जमीन के बदले मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी दी जाएगी। समय बीतता गया रेलवे ने ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का कार्य भी प्रारंभ किया, कई किलोमीटर तक रेलवे की पटरियां बिछाई गईं कई छोटे बड़े रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुए और कई किसानों को मुआवजे के साथ नौकरियां भी दे दी गईं लेकिन सैकड़ों किसान नौकरी से वंचित रह गए। पीड़ित किसान परिवार ने मांगों को लेकर कई बार रेल अधिकारियों को पत्र लिखा, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी गईं।

किसानों का आमरण अनशन

सबके बीच किसानों ने अंदोलन का रास्ता चुना और रेलवे से मांगें मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया तकरीबन एक बर्ष से लगातार किसान आंदोलनरत हैं। पूर्व में भी कई बार किसानों ने रेल रोको जैसे अंदोलन करने के प्रयास किए, लेकिन प्रशासनिक अमले ने उनका रास्ता रोक लिया। बीते 9 दिनों से किसान एक बार फिर रीवा के नवनिर्मित गोविन्दगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर पंडाल लगाकर आमरण अनशन कर रहे हैं। उनका कहना है कि रेलवे जबतक जमीन के बदले परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं देती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

गोविंदगढ़ स्टेशन पहुंचे रेल सुरक्षा आयुक्त

ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत रीवा रेलवे स्टेशन से गोविंदगढ़ स्टेशन तक के रेल मार्ग का मुम्बई रेलवे सर्किल के सीआरएस रेलवे सुरक्षा आयुक्त मनोज अरोरा निरीक्षण करने के लिए आए। उनकी सुरक्षा के लिहाज से आंदोलनकारी किसानों की गतिविधियों और स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन को गोविन्दगढ़ रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्थानों पर धारा 144 लागू करनी पड़ी। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच देर शाम मुम्बई रेलवे सर्किल के सीआरएस रेलवे सुरक्षा आयुक्त मनोज अरोरा ने रेल लाइन का निरक्षण किया।

मैं नहीं हूं सक्षम अधिकारी

रेल लाइन का निरीक्षण करने पहुंचे रेलवे आधिकारी मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह निरीक्षण जब रेलवे के नई लाइन का निर्माण कार्य किया जाता है, तब ट्रेन के आवागमन से पहले रेलवे सुरक्षा आयुक्त के द्वारा सुरक्षा की दृष्टी से जांच की जाती है कि मापदंडों का पालन किया गया है या नहीं। रेलवे परिसर में लगाई गई धारा 144 को लेकर रेल सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। रेलवे के डीआरएम और अन्य अधिकारी ही इस बारे में बता पाएंगे। स्टेशन के बाहर जमीन के बदले नौकरी के लिए अंदोलन कर रहे किसानों को लेकर रेल सुरक्षा आयुक्त मनोज अरोरा ने कहा कि इस मसले में वह सक्षम नहीं हैं। रेलवे ब्रास का जो प्रशासन है वो इस बारे में बेहतर जानकारी दे सकता है। अगर कोई किसान उन्हें आवेदन सौंपता है तो वह उनके पत्र को जरूर मैनेजर को भेज देंगे।

-दवा छिड़काव की हाईटेक व्यवस्था से जोड़ेंगी

अब बुंदेलखंड की महिलाएं खेतों में उड़ाएंगी ड्रोन

छतरपुर। जागत गांव हमार

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो समूह बनाए गए हैं वह अभी तक जमीनीस्तर पर कार्य करते रहे हैं लेकिन अब उनको हाइटेक व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी है। आने वाले दिनों में समूह से जुड़ी महिलाओं के हाथों में ड्रोन नजर आएंगे। इन ड्रोन के माध्यम से वह खेतों में दवा का छिड़काव करेंगी और किसानों की सहायक बनेंगी। नई तकनीक से महिलाओं को जोड़ने के लिए भारत सरकार इस तरह की तैयारी कर रही है। इसे लेकर बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में कृषि विभाग के सहयोग से महिलाओं को ड्रोन की तकनीकि जानकारी देना भी शुरू कर दी गई है। शुरुआती तौर पर महिलाओं को प्राइमरी जानकारी ड्रोन संचालन की दी जा रही है। इसके बाद आगामी तैयारी ड्रोन यूनिटों को लेकर होगी। क्योंकि यह ड्रोन यूनिट पांच से आठ लाख रुपए तक ही है।

ड्रोन का प्रशिक्षण पर प्लानिंग- आपको बता दें कि देशभर में शुरुआती चरण में करीब 15 हजार महिलाओं को ड्रोन से जोड़ा जाएगा। इनमें छतरपुर जिले से 12 से 15 महिलाओं को जोड़ा जा सकता है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी पूरा ध्यान ड्रोन का प्रशिक्षण देने पर है। इसे बाद जो सरकारी की प्लानिंग होगी उसके अनुसार योजना पर काम किया जाएगा।

एक लाख से ज्यादा महिलाएं

छतरपुर जिले में समूहों से जुड़कर महिलाओं ने खुद को आत्मनिर्भर बनाकर दिखाया है। कोई उद्यमी बन गई तो किसी ने अपनी यूनिटें खड़ी कर ली। अब महिलाओं को हाइटेक सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अब समूह की महिलाएं किसानों के खेतों में ड्रोन के माध्यम से दवा का छिड़काव करेंगी। यह ड्रोन की यूनिट भी समूहों के माध्यम से दी जा सकती है। अभी कृषि विभाग के पास जो ड्रोन हैं उनके माध्यम से गांव गांव में जाकर समूहों की महिलाओं को ड्रोन सिस्टम से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिलेभर में करीब दस हजार समूहों से एक लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, जो नवाचार करके खुद को साबित कर रही हैं। टुडर गांव में प्रशिक्षण देने पहुंची टीमकिसानों को भी ड्रोन तकनीक से अवगत कराने के लिए प्रशासन कीटीम छतरपुर जिले के ग्राम टुडर में किसानों के बीच ड्रोन से दवा छिड़काव का प्रदर्शन किया गया।

किसानों दी गई जानकारी

किसानों को बताया गया कि किस तरह ड्रोन तकनीक किसानों के लिए किस तरह उपयोग हो सकती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथों में लगी एलईडी स्क्रीन द्वारा ड्रोन की जानकारी दी गई।

अभी ड्रोन सिस्टम को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल्द ही समूह से जुड़ी महिलाओं के हाथों में ड्रोन नजर आएंगे। पूरे देश में समूहों से जुड़ी करीब 15 हजार महिलाओं को ड्रोन से जोड़े जाने की योजना है। छतरपुर में कृषि विभाग के सहयोग से ड्रोन का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है।

श्याम गौतम, डीपीएम, छतरपुर

जल संसाधन विभाग ने बनाया चार साल का रोड मैप

अब मध्यप्रदेश की 53 लाख हेक्टेयर होगी सिंचाई क्षमता

भोपाल। प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। जल संसाधन विभाग ने सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए अगले चार साल का रोड मैप तैयार कर लिया है। साल 2027 तक मध्यप्रदेश की सिंचाई केपेसिटी 41 लाख से बढ़कर 53 लाख तक पहुंच जाएगी। इसके लिए दिसंबर-2024 तक 43 लाख हेक्टेयर, दिसंबर-2025 तक 46 लाख हेक्टेयर और दिसंबर-2027 तक 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाए जाने का रोडमैप तैयार किया गया है। वर्तमान में जल-संसाधन विभाग के अंतर्गत 41 लाख 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। जल-संसाधन विभाग के अंतर्गत वर्तमान में 40 वृहद, 63 मध्यम और 375 लघु परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल सिंचाई क्षमता 30 लाख हेक्टेयर है। वर्तमान स्थिति में 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आंशिक सिंचाई सुविधा विकसित की जा चुकी है। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। प्रदेश में पानी के अधिकतम उपयोग के लिये सूक्ष्म दाब सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिये 40 वृहद और 53 मध्यम परियोजनाओं में दबावयुक्त पाइप सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते हुए निर्माण किया जा रहा है।

सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराई जा रही

जल-संसाधन विभाग के कुशल प्रबंधन से प्रदेश में निर्मित सिंचाई क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। जल-संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में खरीफ फसल के लिए 3 लाख हेक्टेयर, ग्रीष्मकालीन फसल के लिये 83 हजार हेक्टेयर एवं रबी फसल के लिए निर्धारित लक्ष्य का 34.17 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में हर खेत को पानी उपलब्ध कराने के संकल्प को विभाग द्वारा पूरा किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)